(b) if so, the reasons therefor and details of their demands etc;

(c) whether the management of the Super Bazar has failed to solve the grievances of its employees; and

(d) if so, the steps Government propose to take to solve their grievances?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SARWAR HUSSAIN): (a) A section of employees of the Super Bazar remained on illegal strike from 23-11-90 to 11-12-90.

1. The main demands of the employees included grant of special pay as admissible to Pharmacists, adoption of all Govt. Gazetted Holidays, acceptance of recommendations of Fourth Pay Commission, extension of C. G H. S. benefits and L- T.C. concessions etc.

2. and (d) The management of Super Bazar tried to solve the grievances of employees by offering certain benefits subject to the signing of long term memorandum of settlement and maintenance of industrial peace in September, 1990 but the employees union did not fulfill its part of obligation and went on strike from **23-11-**90.

The management of Super Bazar has appointed a sub-committee comprising of four members of the Managing Committee to look into the demands of the employees within the overall financial capability of the Super Bazar.

Loss of revenue due to unauthorised occupation

223. SHRI RAJNi RANJAN SAHU: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(b) whether it is a fact that during the last three years due to the negligence of the Directorate - of Estates, many cases of unauthorised occupation *;* were unduly delayed which in turn resulted in delay in initiating eviction proceedings and loss to the Government revenue;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the officers responsible for such cases of loss?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DAULAT RAM SARAN): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Collection of licence fees

224. SHRI RAJNT RANJAN SAHU: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased t_0 state:

(a) whether it is a fact that there has been decline in collection of licence fee and also realisation of dues of licence fee from the buildings/shops/ offices under the control of Directorate of Estates; and

(b) if so, the details of licence fee accrued and realised alongwith the details of collection of due_s made during the last three years?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DAULAT RAM SARAN): (a) and (b) A statement showing details of assessment and recovery of licence fee etc. during the last 3 years in respect of General Pool Accommodation (including Office buildings and shops) in Delhi is attached.

Statement

Loss due to non-allotment of flats

225. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several crores of rupees invested in flats purchased by the Directorate of Estates from DDA remained blocked for several years;

(a) if so, the reasons therefor; and

(b) what is the quantum of revenue loss and the number of the allottees who suffered as a result thereof?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DAULAT RAM SARAN): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन

226. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन को दुगना करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द, भाई शाह) : (क) जी नहीं । राज्य ने 1989-90 में हुए 33.7 मिलियन मीटरीटन खाद्यान्न उत्पादन को 1994-95 में 43.0 मिलियन मीटरीटन तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) और (ग) राज्य में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए, समेकित चावल विकास कार्यक्रम, गेंहू, मक्का और कदन्न तथा दालों के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम , राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम आदि जैसी कई योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं । मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को दी जाने वाली सहायता की मात्रा का निर्धारण आठवीं पंचवर्षीय योजना के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् किया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन

227. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष दूध का कितना कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) किसानों से दूध किस दर पर खरीदा जाता है ;

(ग) गाजियाबाद तथा मेरठ से अन्य संस्थानों को कितनी कितनी मात्रा में दूध सप्लाई किया जाता है, तथा किस कीमत पर ;

(घ) क्या उपरोक्त दूध की कीमत के भुगतान में अधिक विलम्ब किया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में वर्षवार, अनुमानित वार्षिक दुग्ध उत्पादन निम्नवत् है :

वर्ष	अनुमानित दुग्ध उत्पादन
	हजार मीटरी टन में
1986-87	8417
1987-88	8595
1988-89 (अंतिम)	8824

(ख) माह अक्टूबर, 1990 के दौरान सरकारी डेरियों द्वारा अदा किया गया औसत उत्पादक मूल्य निम्नवत् है :—

(i) गाय का दूध—3.35 रुपये से 3.83 रुपए प्रति कि० ग्रा० (4% वसा तथा 8.5% ठोस बान्ड फ्रेट)